

## रेलवे में ट्रेन क्लर्कों की पदोन्नति

8939. श्री रामांबतार शास्त्री :  
श्री क० मि० मधकर :  
श्री चन्द्रशेखर सिंह :  
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 फरवरी, 1957 को तत्कालीन रेलवे मन्त्री ने यह घोषणा की थी कि ट्रेन क्लर्कों की असिस्टेंट यार्ड मास्टर्स के पदों पर पदोन्नति की जायेगी क्योंकि उनकी पदोन्नति के लिये केवल यही एक रास्ता है;

(ख) क्या "फेयर डील अवार्ड" नामक उक्त निर्णय के अन्तर्गत 16 मुख्य श्रेणियों के पदों का पुनर्वगीकरण किया जाना था;

(ग) क्या केवल 1½ प्रतिशत ट्रेन क्लर्कों की 250 में 380 रुपये के वेतनमान (असिस्टेंट यार्ड मास्टर्स के वेतनक्रम के बराबर) के पदों पर पदोन्नति की गई है जबकि अन्य श्रेणी के 10 प्रतिशत कर्मचारियों को उक्त वेतनमान दे दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त पंचाट को पूरी तरह से क्रियान्वित न करने और पक्षपात की नीति का पालन करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री जे० मु० पुनावा) :

(क) जी नहीं। घोषणा यह थी कि गाड़ी क्लर्कों के अपने संवर्ग में उच्च ग्रेड के 30 प्रतिशत पदों के अलावा, उनके लिए गार्ड और सहायक यार्ड मास्टर्स के ग्रेड में पदोन्नति सरणी की भी व्यवस्था की जायेगी।

(ख) जी हां। "नये डीजल" से 16 मुख्य श्रेणियों को लाभ हुआ।

(ग) जी नहीं।

(घ) मवाल नहीं उठता।

## पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण

8940. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन के उत्पादन में कमी का मुख्य कारण यह है कि पटसन उत्पादकों को बहुत ही कम मूल्य दिया गया है, जबकि पटसन में बने सामान की कीमत कम नहीं हुई है;

(ख) क्या पटसन उत्पादक किसान और पटसन-मिलों में काम करने वाले श्रमिक पटसन उद्योग के राष्ट्रीयकरण को मांग कर रहे हैं ताकि उत्पादक और उपभोक्ता मूल्यों में विद्यमान अन्तर को समाप्त किया जा सके; और

(ग) इन परिस्थितियों में क्या सरकार का विचार पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) जी, नहीं। इनमें अंतर पिछले दो वर्षों में देश में मौसम की प्रतिकूल दशा और उसके फलस्वरूप कच्चे पटसों की कमी के कारण कच्चे पटसन के मूल्य असाधारण रूप से उच्च स्तर पर चलते रहे जबकि पटसन के माल के मूल्यों में वृद्धि सापेक्षिक रूप में कम रही।

(ख) जी, नहीं। परन्तु पटसन कारखानों की राष्ट्रीय यूनियन ने अपने एक संकल्प में अन्य बातों के साथ यह मांग की है कि कच्चे पटसन तथा निर्यात में राज्य द्वारा व्यापार आरम्भ किया जाये।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।